MATI KRISHNA SAHI) : (a) The case of RIC has already been referred to BIFR. However, the case has not yet been admitted by BIFR.

(b) Yes, Sir.

(c) Since the conditions under SICA for reference to BIFR were fulfilled by RIC, reference *to* BIFR was unavoidable. The Government is, however, continuing to extend financial assistance towards salary and wages of the RIC employees.

EFFECTS OF EXCISE DUTY CONCESSION ON THE CONDITION OF INDUSTRIES

3156. SHRIMATI ILA PANDA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the extent to which the producers have passed on excise duty concessions given in the 1993-94 budget to consumers ;

(b) what is the latest picture of industrial revival in those industries which were hit by recession ; and

(c) the expected growth rate of industrial production during the current financial year and projection for 1994-95 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Excise duties are only one amongst many factors which influence price paid by consumers. A sample study of 10 commonly used consumer articles conducted by the Bureau of Industrial Costs and Prices has revealed that 5 industries viz., biscuits, mopeds, drycell batteries, tooth powder and plastic-moulded luggage have passed on the excise duty relief to the consumers. Two industries, viz.—tea and PVC resin have passed on the relief to the consumers partially-

(b) and (c) On the basis of Index of Industrial Production compiled by Central Statistical Organisation, industrial production has shown an increase of 1.8 per cent during April-August, 1993, on top of a growth of 1.8 per cent during 1992-93. No projection of rate of growth of industrial production has been made for the years 1993-94 and 1994-95.

गुजरात में उद्योगों की स्थापना हेतु लंबित प्रस्ताव :

3157. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नवीन औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित आवेदनों/प्रस्तावों की जिलावार संख्या कितनी है ;

(ख) इन प्रस्तावों में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है,

(ग) इन एककों की स्थापना से रोजगार के कुल कितने अवसर उपलब्ध होने की संभावना है,

(घ) इन संयुक्त उद्यमों के माध्यम से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी,

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है, और

(च) सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक उद्यमों के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बलसाड, बड़ौदा, अहमदाबाद, भडौच, पंचमहल, जूनागढ़, महसाणा, सूरत, बनासकाठा, अमरेली और कलोल जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाईसेंस के लिए 38 आवेदन लम्बित पड़े हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त प्रस्तावों के संदर्भ में प्रस्तावित अचल पूंजी निवेश की राशि और प्रस्तावित रोजगार क्रमश : 666.29 करोड़ रुपए और 15014 व्यक्ति है।

(घ) और (ङ) संयुक्त उपक्रम हेतु विदेशी सहयोग के प्रस्तावों में परियोजना के स्थापना